



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 25, 2017/कार्तिक 3, 1939

No. 282]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2017/KARTIKA 3, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2017

सं. 37/2015-2020

विषय : क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा ईपीसीजी स्कीम के तहत संस्थापन प्रमाण-पत्र को स्वीकार किया जाना जिसमें संस्थापन प्रमाण पत्र 18 माह से आगे प्रस्तुत किया जाता है।

फा. सं. 18/42/एएम-18/पी-5.—विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 2.58 के साथ पठित पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार जनहित में एतद्वारा ईपीसीजी स्कीम के तहत संस्थापन प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाने से संबंधित प्रक्रियाओं में निम्नलिखित एककालिक छूट प्रदान करते हैं:—

- (1) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारकों को संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिसमें क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्धारित समयावधि के अंदर आयातित पूंजीगत माल के संस्थापन को दर्शाया गया हो।
- (2) पूंजीगत माल के संस्थापन के प्रमाणपत्र के संबंध में प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 5.04 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है—
 - (क) प्राधिकार पत्र धारक आयात पूरा करने की तारीख से 6 महीने के भीतर प्राधिकार पत्र धारक के विकल्प के अनुसार क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी या स्वतंत्र सनदी अभियंता से एक प्रमाण-पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बात की पुष्टि हो कि पूंजीगत माल को प्राधिकार पत्र धारक या उसके सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) की फैक्टरी/परिसर में अधिष्ठापित कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु उक्त अवधि को एक बार और 12 महीने की अधिकतम अवधि के लिए बढ़ा सकता है। जहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ पंजीकृत कोई इकाई सनदी अभियंता के प्रमाण-पत्र का चयन करती है, वहां प्राधिकार क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को प्रमाण पत्र की एक प्रति सूचना/अभिलेख के लिए भेजेगा।
 - (ख) कलपुर्जों के आयात के मामले में, प्राधिकार पत्र धारक द्वारा संस्थापन प्रमाण-पत्र आयात की तिथि से तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

- 3) जहां निर्यातक इस निर्धारित समय सीमा में संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हो वहां क्षेत्रीय प्राधिकारी ऐसे प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने में असमर्थ है। इसमें छूट दिए जाने के निवेदन डीजीएफटी मुख्यालय में प्राप्त होते हैं, जिससे कठिनाई और विलंब होता है।
- 4) यह निर्णय लिया गया है कि प्रक्रिया में एक बार छूट देते हुए, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी इस समय सीमा के आगे प्रस्तुत संस्थापन प्रमाणपत्र क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रति प्राधिकार पत्र 5000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करने पर स्वीकार कर सकता है जो निम्नलिखित के अधीन है:
 - (i) पूंजीगत माल आयात की तिथि से 18 माह की अवधि के अंदर संस्थापित किया गया है परंतु क्षेत्रीय प्राधिकारी को संस्थापन प्रमाण पत्र आयात की तारीख से 18 माह प्रस्तुत किया गया है।
 - (ii) प्राधिकार पत्र धारक क्षेत्रीय प्राधिकारी के समक्ष संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में होने वाले विलंब के उचित कारणों का उल्लेख करता है।
 - (iii) क्षेत्रीय प्राधिकारी को संस्थापन प्रमाणपत्र 31.3.2018 को अथवा इससे पहले प्रस्तुत किया जाता है।
 - (iv) ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र क्षेत्रीय प्राधिकारी/सीमाशुल्क प्राधिकारी/किसी अन्य अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण के अधीन नहीं है/अधिनिर्णीत नहीं है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:—

ईपीसीजी स्कीम के तहत संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब की माफी हेतु एक बारगी छूट प्रदान की जा रही है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 25th October, 2017

No. 37/2015-2020

Sub : Acceptance of installation certificate under EPCG scheme by the RAs wherein installation certificate is submitted beyond 18 months.

F. No. 18/42/AM-18/P-5.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.04 read with Paragraph 2.58 of FTP 2015-20, the Director General of Foreign Trade in Public interest hereby makes the following one time relaxations in procedures in respect of acceptance of installation certificate under EPCG Scheme.

1. The EPCG authorization holders are required to submit the installation certificate showing installation of the imported capital goods to the RA within prescribed time period.
2. Para 5.04 of the Handbook of Procedures 2015-20 regarding certificate of installation of capital goods stated is as under:
 - a. Authorization holder shall produce, within six months from date of completion of import, to the concerned RA, a certificate from the jurisdictional Central Excise Authority or an independent Chartered Engineer, at the option of the authorization holder, confirming installation of capital goods at factory/premises of authorization holder or his supporting manufacturer(s). The RA may extend the said period for producing the certificate by a maximum period of another 12 months. Where a unit registered with Central Excise opts for independent Chartered Engineer's certificate, the authorization holder shall send a copy of the certificate to the jurisdictional Central Excise Authority as intimation/record.
 - b. In the case of import of spares, the installation certificate shall be submitted by the Authorization holder within a period of three years from the date of import.
3. Where the exporter is unable to submit the installation certificate within this prescribed time limit, the RA is not able to accept such certificates. Such requests for condonation are received in DGFT Hqrs. which causes hardship and delay.
4. It has been decided that in relaxation of the procedure as onetime condonation, the RAs concerned may accept the installation certificate submitted beyond the time limit on payment of penalty of Rs. 5000/- per authorization to RA, subject to the following:
 - i. The capital goods have been installed within the period of 18 months from the date of imports but the installation certificate has been submitted to RA beyond 18 months from the date of import.

- ii. The authorization holder submits to RA bonafide reasons for delay in submission of installation certificate.
- iii. The installation certificate is submitted to RA on or before 31.03.2018.
- iv. The EPCG authorization is not under investigation/adjudicated by RA/customs authority/any other investigating agency.

Effect of the Public Notice: Onetime relaxation for condonation of delay in submission of installation certificate under EPCG Scheme is being provided.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade